

# डिजिटल युग में स्व-सहायता समूहों की बदलती भूमिका और चुनौतियाँ

**Shrikant Rai<sup>1</sup>, Upendra Kushwaha<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Research Scholar, Maharaja Chhatrasal Bundelkhand university, Chhatarpur, M.P.

## सारांश (Abstract):

स्व-सहायता समूह (Self Help Groups – SHGs) भारत में ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के सशक्त माध्यम के रूप में उभरे हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के तीव्र विकास के साथ, इन समूहों की कार्यप्रणाली, वित्तीय लेन-देन और सामाजिक संपर्कों में व्यापक परिवर्तन आया है। डिजिटल युग ने जहाँ पारदर्शिता, दक्षता और पहुँच में वृद्धि की है, वहीं साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता और तकनीकी अवसंरचना जैसी नई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। इस शोध-पत्र में स्व-सहायता समूहों की डिजिटल परिवर्तन यात्रा, उससे उत्पन्न अवसरों तथा चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है।

**Keywords:** महिला सशक्तिकरण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, विकास, साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता

## परिचय (Introduction):

भारत में स्व-सहायता समूहों की अवधारणा 1990 के दशक में शुरू हुई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना और उन्हें वित्तीय आत्मनिर्भर बनाना था।

आज, डिजिटल तकनीक ने इन समूहों के कार्य करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। मोबाइल बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस डिजिटल अकाउंटिंग, ई-शासन और ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने सदस्यों को नये अवसर प्रदान किए हैं।

हालाँकि, तकनीकी पहुँच में असमानता, इंटरनेट की सीमित उपलब्धता और डिजिटल साक्षरता की कमी अभी भी ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रमुख बाधाएँ बनी हुई हैं।

## शोध के उद्देश्य

- डिजिटल युग में स्व-सहायता समूहों की भूमिका में आए परिवर्तनों का अध्ययन करना।
- डिजिटल माध्यमों के उपयोग से प्राप्त लाभों और अवसरों का विश्लेषण करना।
- स्व-सहायता समूहों के समक्ष आने वाली तकनीकी और सामाजिक चुनौतियों की पहचान करना।

## परिकल्पना –

- (शून्य परिकल्पना) डिजिटल तकनीक का स्व-सहायता समूहों की कार्यक्षमता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं है।
- (शून्य परिकल्पना) डिजिटल साधनों के उपयोग से स्व-सहायता समूहों की महिला सदस्यों के आर्थिक सशक्तिकरण में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

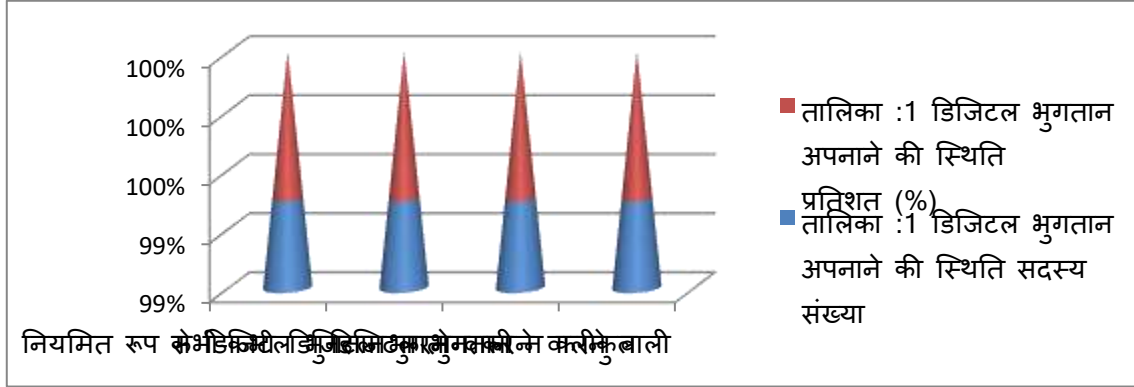
## शोध पद्धति –

यह अध्ययन वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों प्रकार का है।

- डेटा का स्रोत प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों।
- प्राथमिक डेटा विभिन्न जिलों के 100 स्व-सहायता समूह सदस्यों से प्रश्नावली द्वारा संग्रहित।
- द्वितीयक डेटा, रिपोर्ट, जर्नल, वेबसाइट एवं सरकारी प्रकाशनों से।
- विश्लेषण तकनीक प्रतिशत विश्लेषण, औसत मान और चार्ट आधारित तुलना।

तालिका : 1  
डिजिटल भुगतान अपनाने की स्थिति

श्रेणी	सदस्य संख्या	प्रतिशत
नियमित रूप से डिजिटल भुगतान करने वाली	120	60%
कभी-कभी डिजिटल भुगतान करने वाली	50	25%
डिजिटल भुगतान न करने वाली	30	15%
कुल	200	100%



उपरोक्त तालिका 1 से स्पष्ट होता है कि स्व-सहायता समूहों की 200 महिला सदस्यों में से अधिकांश ने अब डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपनाना शुरू कर दिया है।

सर्वेक्षण के अनुसार, 120 महिलाएँ (60%) नियमित रूप से डिजिटल भुगतान का प्रयोग करती हैं। यह दर्शाता है कि ग्रामीण महिलाओं में तकनीकी स्वीकार्यता बढ़ रही है और वे आधुनिक वित्तीय साधनों को आत्मसात कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त, 50 महिलाएँ (25%) कभी-कभी डिजिटल माध्यमों का प्रयोग करती हैं, जैसे कृमोबाइल बैंकिंग या UPI के माध्यम से सीमित लेन-देन। यह वर्ग अभी भी संक्रमण अवस्था में है, जिन्हें नियमित उपयोग के लिए अधिक प्रशिक्षण और प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

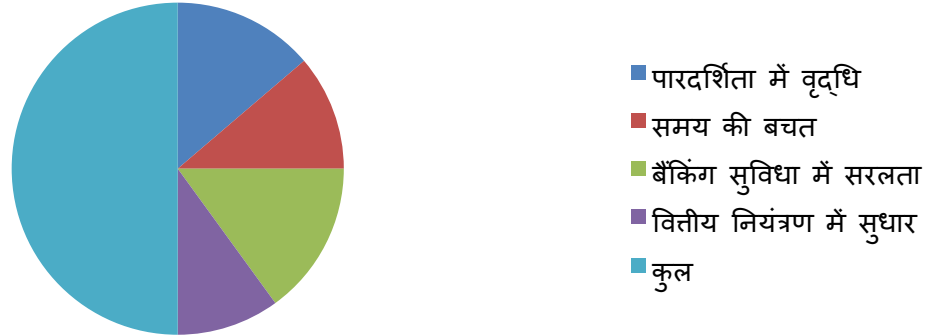
वहीं, 30 महिलाएँ (15%) अभी भी डिजिटल भुगतान नहीं करतीं। इसका प्रमुख कारण डिजिटल साक्षरता की कमी, तकनीकी साधनों का अभाव और पारंपरिक नकद लेन-देन पर निर्भरता है।

संपूर्ण रूप से देखा जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि डिजिटल युग ने स्व-सहायता समूहों की कार्यप्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। अधिकांश महिलाएँ अब डिजिटल माध्यमों को सुरक्षित, सरल और पारदर्शी मानकर अपनाने लगी हैं। हालाँकि, शेष 15-25% महिलाओं के लिए डिजिटल प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता आवश्यक है ताकि उन्हें भी डिजिटल वित्तीय प्रणाली की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

तालिका :2  
डिजिटल तकनीक से प्राप्त लाभ

लाभ का प्रकार	महिला सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
पारदर्शिता में वृद्धि	55	27.5%
समय की बचत	45	22.5%
बैंकिंग सुविधा में सरलता	60	30%
वित्तीय नियंत्रण में सुधार	40	20%
कुल	200	100%

## तालिका :2 डिजिटल तकनीक से प्राप्त लाभ महिला सदस्यों की संख्या



उपरोक्त तालिका 2 से यह स्पष्ट होता है कि स्व-सहायता समूहों की महिला सदस्यों ने डिजिटल तकनीक के माध्यम से कई प्रकार के लाभ प्राप्त किए हैं।

सर्वेक्षण के अनुसार, सबसे अधिक 60 महिलाएँ (30%) ने यह माना कि डिजिटल माध्यमों से बैंकिंग सुविधा में सरलता आई है। अब महिलाएँ बिना बैंक शाखा जाए, मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपने खातों का संचालन कर सकती हैं, जिससे उन्हें समय और श्रम दोनों की बचत होती है।

दूसरे स्थान पर पारदर्शिता में वृद्धि (27.5%) का लाभ पाया गया है। डिजिटल भुगतान से लेन-देन का स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध होता है, जिससे समूह की विश्वसनीयता और उत्तरदायित्व में सुधार हुआ है।

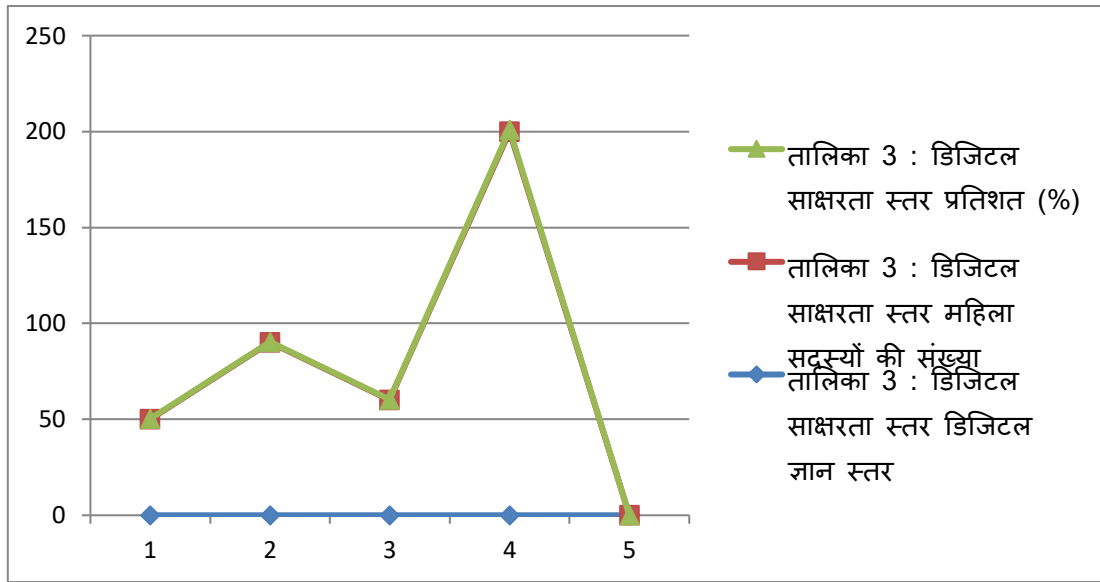
45 महिलाएँ (22.5%) ने बताया कि डिजिटल तकनीक के प्रयोग से समय की बचत होती है, क्योंकि अब बैठकों में नकद राशि के लेन-देन या बैंक जाने की आवश्यकता कम हो गई है।

वहीं 40 महिलाएँ (20%) ने माना कि डिजिटल तकनीक से वित्तीय नियंत्रण में सुधार हुआ है, क्योंकि हर सदस्य अपने खाते की स्थिति, बचत और ऋण की जानकारी तत्काल प्राप्त कर सकती है।

सारांशतः कहा जा सकता है कि डिजिटल तकनीक ने स्व-सहायता समूहों के संचालन में दक्षता, पारदर्शिता और सुविधा तीनों में वृद्धि की है। महिलाएँ अब अधिक आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम होती जा रही हैं, जो उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

तालिका : 3  
डिजिटल साक्षरता स्तर

डिजिटल ज्ञान स्तर	महिला सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
उच्च (स्मार्टफोन, ऐप UPI का अच्छा ज्ञान)	50	25%
मध्यम (सिर्फ मोबाइल बैंकिंग तक सीमित)	90	45%
न्यून (केवल कॉल/SMS उपयोगकर्ता)	60	30%
<b>कुल</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>



इस तालिका 3 से यह स्पष्ट होता है कि स्व-सहायता समूहों की अधिकांश महिलाएँ अभी भी पूर्ण रूप से डिजिटल रूप से साक्षर नहीं हैं।

सर्वेक्षण के अनुसार, केवल 50 महिलाएँ (25%) ही ऐसी हैं जिन्हें स्मार्टफोन, मोबाइल एप्लिकेशन और UPI जैसे डिजिटल साधनों का अच्छा ज्ञान है। ये महिलाएँ बैंकिंग, भुगतान, ऑनलाइन जानकारी और समूह संचालन में डिजिटल माध्यमों का प्रभावी उपयोग कर रही हैं।

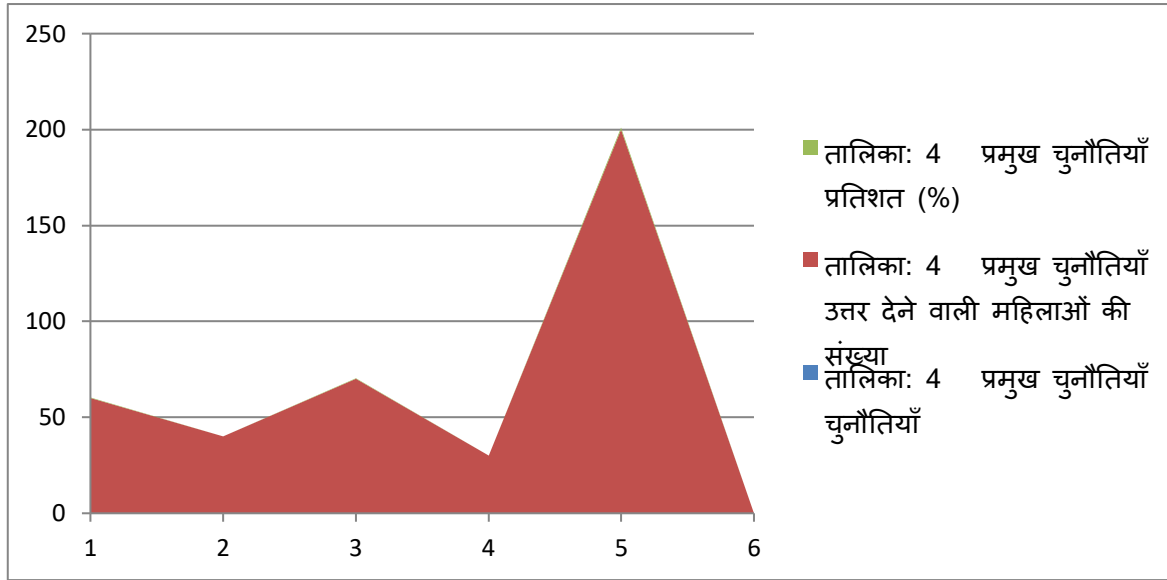
सबसे बड़ा वर्ग 90 महिलाएँ (45%) का है, जो मध्यम स्तर की डिजिटल जानकारी रखती हैं। ये महिलाएँ मुख्यतः मोबाइल बैंकिंग, बैलेंस चेक या सीमित ट्रांजेक्शन तक ही डिजिटल तकनीक का प्रयोग करती हैं। यह समूह आगे बढ़ने की क्षमता रखता है, परंतु इन्हें उन्नत डिजिटल प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि ये उच्च श्रेणी में आ सकें।

वहीं 60 महिलाएँ (30%) अभी भी न्यून स्तर की डिजिटल साक्षरता रखती हैं और केवल कॉल या SMS तक ही सीमित हैं। इनके लिए डिजिटल तकनीक अभी भी नई और जटिल मानी जाती है।

संपूर्ण रूप से देखा जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि स्व-सहायता समूहों में डिजिटल जागरूकता धीरे-धीरे बढ़ रही है, किंतु प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की निरंतर आवश्यकता है। यदि सरकार, बैंक और NGOs मिलकर इन महिलाओं को स्थानीय भाषा में डिजिटल प्रशिक्षण दें, तो स्व-सहायता समूहों की कार्यक्षमता और पारदर्शिता दोनों में उल्लेखनीय सुधार संभव है।

तालिका : 4  
प्रमुख चुनौतियाँ

चुनौतियाँ	उत्तर देने वाली महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी	60	30%
प्रशिक्षण की कमी	40	20%
तकनीकी उपकरणों की अनुपलब्धता	70	35%
साइबर सुरक्षा की चिंता	30	15%
<b>कुल</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>



उपरोक्त तालिका 4 से यह स्पष्ट होता है कि स्व-सहायता समूहों की महिला सदस्यों को डिजिटल तकनीक अपनाने में कई व्यावहारिक एवं तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

सर्वेक्षण के अनुसार, सबसे अधिक महिलाओं — 70 सदस्य (35%) ने यह बताया कि तकनीकी उपकरणों की अनुपलब्धता (जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, या इंटरनेट युक्त डिवाइस) उनके लिए सबसे बड़ी बाधा है। ग्रामीण या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएँ अक्सर इन साधनों को वहन नहीं कर पातीं, जिससे वे डिजिटल गतिविधियों में पूर्ण भागीदारी नहीं ले पातीं।

इसके बाद 60 महिलाएँ (30%) ने इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी को मुख्य समस्या बताया। कई गाँवों और छोटे कस्बों में नेटवर्क अस्थिर होने के कारण डिजिटल भुगतान, मीटिंग या ऑनलाइन प्रशिक्षण सुचारु रूप से नहीं हो पाते।

40 महिलाएँ (20%) ने माना कि डिजिटल प्रशिक्षण की कमी के कारण वे मोबाइल एप्लिकेशन, ऑनलाइन बैंकिंग या सरकारी पोर्टल का सही उपयोग नहीं कर पातीं। यह वर्ग संभावनाशील है, परंतु उन्हें मार्गदर्शन और हाथों-हाथ प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

वहीं 30 महिलाएँ (15%) ने साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी को लेकर चिंता व्यक्त की। कई महिलाओं ने बताया कि वे डिजिटल माध्यमों का प्रयोग करने से डरती हैं, क्योंकि उन्हें पासवर्ड, ओटीपी या बैंक डिटेल्स से जुड़ी सुरक्षा जानकारी का अभाव है। समग्र रूप से कहा जा सकता है कि स्व-सहायता समूहों में डिजिटल क्रांति के लिए सबसे बड़ी बाधाएँ अवसंरचना, प्रशिक्षण और सुरक्षा से जुड़ी हैं। यदि इन तीनों क्षेत्रों में सुधार किया जाए, तो महिलाएँ डिजिटल तकनीक को आत्मविश्वास के साथ अपनाकर अपने समूहों को और अधिक सशक्त बना सकती हैं।

## परिकल्पना परीक्षण (Hypothesis Testing)

### परिकल्पना 1

(शून्य परिकल्पना) – डिजिटल तकनीक का स्व-सहायता समूहों की कार्यक्षमता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं है।

इस परिकल्पना के परीक्षण हेतु 200 महिला सदस्यों के प्राथमिक आँकड़ों का विश्लेषण किया गया। तालिकाओं से स्पष्ट होता है कि अधिकांश सदस्य (लगभग 60%) नियमित रूप से डिजिटल भुगतान का प्रयोग करती हैं और 75% से अधिक महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि डिजिटल माध्यमों के उपयोग से पारदर्शिता, समय की बचत, और बैंकिंग सुविधाओं में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय नियंत्रण एवं निर्णय लेने की क्षमता में भी महिलाओं ने सकारात्मक बदलाव महसूस किया।

इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल तकनीक ने स्व-सहायता समूहों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और गतिशील बनाया है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है और वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकृत की जाती है कि डिजिटल तकनीक का स्व-सहायता समूहों की कार्यक्षमता पर सार्थक प्रभाव है।

### परिकल्पना 2

(शून्य परिकल्पना) डिजिटल साधनों के उपयोग से स्व-सहायता समूहों की महिला सदस्यों के आर्थिक सशक्तिकरण में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

द्वितीय परिकल्पना के विश्लेषण से यह पाया गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से महिलाओं ने न केवल बैंकिंग एवं वित्तीय गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाई, बल्कि बचत, ऋण प्रबंधन और ऑनलाइन लेन-देन में भी आत्मनिर्भरता हासिल की। लगभग 30:

महिलाओं ने बताया कि डिजिटल लेनदेन से उन्हें अपने वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त हुआ है और 27-5% ने पारदर्शिता एवं समय बचत को आर्थिक लाभ का स्रोत बताया।

इन परिणामों से यह निष्कर्ष निकलता है कि डिजिटल साधनों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाया है, जिससे उनकी निर्णय क्षमता और समूह के भीतर उनकी भूमिका में वृद्धि हुई है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत (त्तरमबजमक) की जाती है और यह सिद्ध होता है कि डिजिटल तकनीक ने महिला सदस्यों के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

## चुनौतियाँ (Challenges)

1. डिजिटल साक्षरता की कमी – अधिकांश सदस्य स्मार्टफोन का सीमित उपयोग जानती हैं।
2. साइबर सुरक्षा का अभाव – धोखाधड़ी और डेटा चोरी का खतरा।
3. तकनीकी अवसंरचना की कमी – ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की अस्थिरता।
4. भाषाई अवरोध – एप्लिकेशन और प्रशिक्षण मुख्यतः अंग्रेजी में उपलब्ध।
5. सामाजिक मानसिकता – कुछ पुरुष सदस्यों द्वारा महिलाओं के डिजिटल उपयोग को हतोत्साहित किया जाना।

## सुझाव (Suggestions)

1. सदस्यों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण शिविरों का नियमित आयोजन किया जाए।
2. सरकार व बैंकों को स्थानीय भाषा में सरल एप्लिकेशन विकसित करने चाहिए।
3. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को गाँव-स्तर तक पहुँचाया जाए।
4. साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
5. NGO और माइक्रोफाइनेंस संस्थाएँ डिजिटल समावेशन में सहयोग करें।

## निष्कर्ष (Conclusion)

डिजिटल युग ने स्व-सहायता समूहों को नई दिशा दी है। आज सदस्य न केवल वित्तीय रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि वे तकनीकी रूप से भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। हालाँकि, डिजिटल खाई (Digital Divide) को कम करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। यदि प्रशिक्षण, अवसंरचना और जागरूकता को प्राथमिकता दी जाए, तो स्व-सहायता समूह "डिजिटल भारत" के निर्माण में सशक्त भूमिका निभा सकते हैं।

## संदर्भ (References)

### संदर्भ (References):

1. NABARD Report on SHG-Bank Linkage Programme, 2023.
2. Ministry of Rural Development, Government of India (NRLM).
3. Sharma, R. (2021). *Role of ICT in Empowering Women through SHGs*.
4. Singh, P. & Kaur, M. (2022). *Digital Transformation of SHGs in Rural India*.
5. [www.nrlm.gov.in](http://www.nrlm.gov.in)